मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

उफनते सीवरों से तंग दो नम्बर वासियों ने लगाया जाम 2
लड़की को प्रेमजाल में फंसा उसकी हत्या कर नहर में फेंका 4
मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ़्तारी हिंदी फिल्म के स्क्रीनशॉट के लिए हुई 5
कलम बिकने लगी तो पत्रकारिता का काम तमाम 6
पीएमओ सविता यादव ने लिया प्रशंसा का राष्ट्रीय प्रमाणपत्र 8

वर्ष 36 | अंक 35 | फरीदाबाद | 10-16 जुलाई 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

ईएसआई कार्पोरेशन मेडिकल कमिश्नर

दीपक शर्मा को नहीं सुहातीं उन्नत मेडिकल सेवायें

फ़रीदाबाद (म.मो.) सरकारी सिस्टम ने कई बार नालायक व हरामखोर लोग तिकड़मबाजी के बल पर इतने उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं जिसके कि वे लायक नहीं होते। ऐसे ही लोगो में से एक हैं डॉक्टर दीपक शर्मा एमबीबीएस। अपनी शैक्षणिक योग्यता के बल पर वे केवल किसी डिस्पेंसरी में बैठ कर मरीज़ देखने के लायक भर ही हैं। ईएसआई कॉर्पोरेशन में वे भर्ती भी इसी काम के लिये हुए थे, परन्तु सरकारी सिस्टम में जुगाड़बाज़ी के बल पर आज वे कार्पोरेशन के मेडिकल कमिश्नर बन बैठे हैं।

कॉर्पोरेशन काडर के अफ़सरों में यह सर्वोच्च पद है। इसके ऊपर केवल डायरेक्टर जनरल का पद होता है जिस पर दो-तीन साल के लिये कोई आईएएस अफ़सर नियुक्त होता है। बाहर से आनेवाले आईएएस अफ़सर को मेडिकल कमिश्नर पद पर बैठे लोग हर तरह से मिसगाईड करने का प्रयास करते हैं। इस पद पर आने वाला जो अफ़सर अधिक चौकन्ना एवं समझदार न हो तो उसे ये लोग

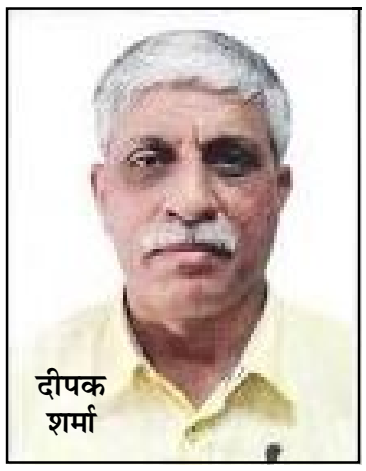
दीपक शर्मा

अपने मुताबिक घुमाते रहते हैं। डीजी को घुमाने में माहिर पहले कटारिया नामक एक एमसी होता था जिसे डीजी ने पहचान कर खुड्डे लाइन लगा दिया था। परन्तु अब उसकी जगह उससे भी शातिर दीपक शर्मा बतौर एमसी आ बैठा है।

इस तरह के अयोग्य लोग जिन्होंने कभी डिस्पेंसरी से ऊपर के मेडिकल सिस्टम को देखा तक नहीं होता वे अति उच्चस्तरीय मेडिकल संस्थानों के सर्वेसर्वा जब बन जाते हैं तो इनके दिमाग खराब हो जाते हैं। ये लोग, जो सिस्टम के लिये पूर्णतया अनुपयोगी होते हैं, अपने आप को उपयोगी सिद्ध करने के लिये कुछ भी उलटे-पुलटे काम करते रहते हैं। ऐसे ही नालायक लोगों के गिरोह में फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज को खुलने से रोकने के भरसक प्रयास किये थे। परन्तु आज इस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उत्कृष्ट परिणामों से जहां एक ओर केन्द्रीय श्रम मंत्री, श्रम सचिव तथा डीजी के अतिरिक्त मुख्यालय में बैठे अनेकों अफ़सर अति प्रसन्न एवं गर्वित हैं वहीं हरियाणा सरकार भी इसकी ओर ललचाई नज़रो से देखती रहती है।

इसके बावजूद दीपक शर्मा जैसी निकृष्ट प्रवृत्ति का भी एक गिरोह मुख्यालय में सक्रिय है। इसका पूरा प्रयास रहता है कि किस प्रकार इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को उजाड़ा जाय। 'मज़दूर मोर्चा' के 19-25 जून के अंक में **'डॉक्टर दीपक शर्मा जैसे निकृष्ट एवं हरामखोर जहां इंचार्ज होते हैं वहां बिस्तर खाली ही रहते हैं'** शीर्षक से प्रकाशित समाचार में बताया गया था कि इस दीपक शर्मा ने किस प्रकार अच्छे-भले बसई दारापुर अस्पताल का बेड़ागर्क किया था। शत प्रतिशत ऑक्यूपेंसी वाले अस्पताल को 50 प्रतिशत पर ला खड़ा किया था। अब इनका लक्ष्य देश भर के तमाम, उत्कृष्ट सेवायें देने वाले अस्पतालों का सत्यानाश करना है।

अपने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये इस अज्ञानी ने कॉर्पोरेशन की तबादला नीति, जो कि साधारण डॉक्टरों (जीडीएमओ) के लिये बनाई गई थी, उसमें मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की फेकल्टी को भी लपेट लिया है। इसके तहत ये साहब एनसीआर में तैनात उन तमाम प्रोफेसरों आदि को इस क्षेत्र से बाहर कहीं दूर-दराज़ तैनात कर देना चाहते हैं।

ऐसा करके शायद दीपक शर्मा उन तमाम अति विद्वान एवं वरिष्ठ डॉक्टरों को यह अहसास कराना चाहते हैं कि साधारण एमबीबीएस होने के बावजूद वे तमाम प्रोफेसरों को धूल चटाने में सक्षम हैं। इस तबादला नीति के तहत उत्तर भारत में तैनात दक्षिण भारत में तथा दक्षिण वाले उत्तर में आयेंगे। जाहिर है कि ऐसे में न मरीज़ डॉक्टर की भाषा समझेगा न डॉ. मरीज की।

फेकल्टी के तबादले नहीं हुआ करते

फेकल्टी यानी छात्रों को पढ़ाने वाले व मरीज़ों का इलाज करने वाले वरिष्ठ डॉक्टरों की नियुक्ति जिस संस्थान में होती है, वह उस संस्थान के साथ जुड़कर न केवल पढ़ाने व इलाज करने का काम करते हैं बल्कि खुद भी पढ़ने व रिसर्च करने का काम भी करते हैं। इसके लिये उन्हें स्थायित्व की आवश्यकता होती है। संस्थान की प्रयोगशालाओं में उनके तरह-तरह के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। इनके रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल्स में छपते रहते हैं। फरीदाबाद के अनेकों डॉक्टरों के पेपर लैनसेट नामक अति प्रतिष्ठित ब्रिटिश जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं और कई पाइप लाइन में हैं।

इन प्रोफेसरों के काम-काज, मेहनत व लगन को देखते हुए आईसीएमआर जैसे अनेकों संगठनों ने इस कॉलेज को कई प्रोजेक्ट दे रखे हैं। इन प्रोजेक्टों के लिये ईएसआई को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता बल्कि बाहर से आने वाला पैसा कॉलेज एवं अस्पताल के बड़े काम आता है। फेकल्टी की लगन व मेहनत को देखते हुए ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इन्डिया ने इस अस्पताल को न्यूरो सर्जरी शुरू करने के लिये दो करोड़ के उपकरण खरीद कर दिये हैं, जिससे खबर लिखे जाने तक यहां पांच मरीज़ों की कामयाब न्यूरो सर्जरी हो चुकी है जबकि इस विभाग का उद्घाटन होना अभी बाकी है। इसी तरह सेफ़ इन्डिया नामक एनजीओ व एचडीएफसी के द्वारा भी इस अस्पताल को करोड़ों रुपये के अल्ट्रासाऊंड मशीन व एक्सरे आदि के उपकरण उपहार स्वरूप दिये गये हैं। विदित है कि कम्पनियों द्वारा यह पैसा अपने सीएसआर फंड से दिया जाता है।

इन्हीं उपकरणों के बदौलत अब यहां बोन मैरो ट्रांस्प्लांटेशन के भी 15 केस सफलतापूर्वक कर लिये गये हैं। इसे कैंसर का सबसे घातक रोग समझा जाता है। इसके लिये व्यापारिक अस्पताल 30 से 50 लाख तक कुछ भी वसूल सकते हैं। ईएसआई कॉर्पोरेशन खर्चा बचाने के चक्कर में ऐसे मरीजों को रैफ़र न करके मरने के लिये छोड़ दिया करती थी।

संस्थान के डीन डॉक्टर असीम दास के कुशल एवं सहयोगपूर्ण नेतृत्व में सारी फेकल्टी, तमाम अड़चनों के बावजूद न केवल बेहतरीन सेवायें देने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि सेवाओं का विस्तार भी कर रहे हैं। इसी विस्तार में हृदय रोग निदान के लिये कैथलैब भी यहां लगा दी गई है। इसके द्वारा अब तक 120 से अधिक हृदय रोगियों का सफ़लतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। अजब-गजब बात तो यह है कि बढ़ती सेवाओं के लिये प्रोत्साहित करने की अपेक्षा मुख्यालय में बैठे दीपक शर्मा जैसे निकृष्ट अधिकारी इस अस्पताल को आवश्यक तकनीकी एवं नर्सिंग स्टाफ़ तक उपलब्ध नहीं होने दे रहे हैं।

दीपक शर्मा को इस बात का कतई ज्ञान नहीं है कि यदि उन्होंने फेकल्टी के साथ उठा-पटक की तो उनका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, लेकिन इस अस्पताल का जरूर सत्यानाश हो जायेगा। यह भी बसई दारापुर की तरह 50 प्रतिशत पर आ जायेगा। विदित है कि यहां मौजूद बेहतरीन एवं समर्पित फेकल्टी की मार्केट में बहुत मांग है। फेकल्टी वाले यहां नहीं तो कहीं और कमा कर खा लेंगे।

नालायक अफ़सरों से कार्पोरेशन को बचायें श्रम मंत्री

केन्द्रीय श्रम मंत्री होने के नाते ईएसआई कार्पोरेशन का नेतृत्व एवं नियंत्रण पूर्णतया भूपेन्द्र सिंह यादव उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिये चिकित्सा की दृष्टि से मज़दूरों के लिये अति महत्वपूर्ण इस कार्पोरेशन की ओर मंत्री महोदय अपना ध्यान करें, केवल अफ़सरों के भरोसे न रहें। उनके आधीन आने वाले श्रम सचिव तथा कार्पोरेशन के डीजी तो आते-जाते रहते हैं। पिछले दिनों इस स्तर के आये अधिकारियों ने कार्पोरेशन की चिकित्सा सेवाओं में सुधार करने के सराहनीय प्रयास किये हैं। लेकिन असली जरूरत मुख्यालय में स्थाई रूप से जमे बैठे उच्चाधिकारियों को दुरुस्त करने की अधिक है।

डिस्पेंसरी स्तर के डॉक्टर जो दफ्तरों में बैठकर डॉक्टरी भूलकर पूरी तरह से बाबू बन चुके हैं, वे इस लायक नहीं हैं कि कारपोरेशन की उन्नत होती चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकताओं को समझ सकें। ये लोग आईसीयू, डायलेसिस तथा रेडियोलॉजी इत्यादि को पीपीपी मोड द्वारा ही चलाने में अक्लमंदी समझते हैं। चार कर्मचारियों का काम एक से और प्रशिक्षित स्टाफ़ की जगह अर्ध प्रशिक्षित स्टाफ़ से काम लेकर पैसा बचाने को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा आवश्यक चिकित्सीय उपकरण खरीदते समय ये लोग सस्ते के चक्कर में घटिया से घटिया एवं पुरानी तकनीक के उपकरण खरीदने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर की फ़िजूलखर्चियां करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चिकित्सा सेवाओं में सुधार पर खर्च करने पर इनकी जान निकलती है।

मंत्री महोदय को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में ही स्थित एम्स संस्थान को देख लें कि उसे कौन लोग चला रहे हैं। वहां का डायरेक्टर कोई डिस्पेंसरी स्तर का नालायक न होकर उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर ही हो सकता है। इसके विपरीत कार्पोरेशन के तमाम मेडिकल कॉलेजों के सिर पर जहां पहले कटारिया जैसा नालायक बैठा रखा था वहीं अब उससे भी बड़ा नालायक दीपक शर्मा बैठा दिया गया है। अपने मन में पनपती हीन भावनाओं के चलते ऐसे उच्चाधिकारी उच्च चिकित्सीय मानकों वाले प्रोफेसरों को भला कैसे पसंद कर सकते हैं?

उसी के चलते फेकल्टी को भर्ती करने, उन्हें पदोन्नतियां व वेतनभत्ते देने में अनावश्यक अड़ंगेबाजी करते हैं। ये नालायक अधिकारी इतना तक भी देखने की कोशिश नहीं करते कि बगल में ही स्थित एम्स जैसे संस्थानों में फेकल्टी को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं। इसी के चलते कार्पोरेशन के संस्थानों से फेकल्टी वाले एम्स जैसे संस्थानों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं।

कार्पोरेशन के उच्च चिकित्सीय संस्थानों को न केवल बनाये रखने बल्कि उन्हें और उन्नत करने के लिये श्रम मंत्री महोदय को विशेष ध्यान देने की आवशयकता है।